



मु.मंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर की झीलों और जलाशयों को वर्ष पर्यंत पानी से भरा रखने के उद्देश्य से लाई गई परियोजना "देवास थर्ड-फोर्थ" का शुक्रवार को शिलान्यास किया। इस परियोजना के लिए सरकार ने 1690 करोड़ रु. का बजट आवंटित किया है। इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी एवं असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद थे।

मु.मंत्री भजन लाल ने देवास प्रोजेक्ट के तीसरे व चौथे चरण का शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री ने कहा, 1690 करोड़ रु. की लागत वाली यह योजना पूरी होने के बाद उदयपुर की झीलें हमेशा भरी रहेंगी

उदयपुर/मावली, 1 मार्च (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर की झीलों को हमेशा लबालब रखने और पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने वाली 1690 करोड़ की देवास थर्ड-फोर्थ परियोजना का शिलान्यास किया। शुक्रवार को गोंगुदा में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि, इस परियोजना के मूर्त रूप लेने के बाद उदयपुर में पानी की कोई कमी नहीं आएगी। राजस्थान आने वाला हर तीसरा व्यक्ति उदयपुर आता है।

प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि, भारत दुनिया का "बैडिंग डेस्टिनेशन" बने और उदयपुर बैडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर भी रहा है। महाराणा प्रताप को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, महाराणा प्रताप से संबंधित सभी स्थानों को सर्किट के तहत पर्यटन स्थल बनाने का काम हमारी सरकार करेगी।

- मुख्यमंत्री ने गोंगुदा में हुए समारोह में कहा कि, इस परियोजना से उदयपुर में कभी पानी का संकट नहीं आएगा और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- कार्यक्रम में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने देवास थर्ड-फोर्थ परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही जमीन के काश्तकारों से कहा कि, जिन लोगों की जमीन इस परियोजना के डूब क्षेत्र में आएगी, हम उन किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे। उनको पूरा हक हम देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि, बांसवाड़ा जिले में स्थित माहीबांध में आईलैंड्स हैं, उसे भी पर्यटकों के लिए विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री ने गोंगुदा में भी कहा कि, कालेज का लोकार्पण भी किया।

समारोह से पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंगुदा में महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली के दर्शन किए और मंशापूर्णा नीलकंठ

महादेव मंदिर में विधिवत् पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण भी किया।

असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर की झीलों के लिए देवास परियोजना का महत्व बताते हुए कहा कि, इस परियोजना से उदयपुर की झीलें ही लबालब नहीं होंगी, बल्कि उदयपुर जिले के कई जलाशयों को हम हमेशा भरा रख सकेंगे और लोगों को पीने का भरपूर पानी भी मिल सकेगा।

जल संसाधन विभाग के मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि देवास तृतीय

एवं चतुर्थ परियोजना की अनुमानित लागत 1690.55 करोड़ है एवं 44 माह की समयवधि में इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है। इससे 1000 एम.सी.एफ.टी. वार्षिक जल अपवर्तन उदयपुर शहर की झीलों में किया जाएगा। परियोजना की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जारी हो चुकी है।

समारोह में जल संसाधन विभाग के मंत्री सुरेश सिंह रावत के साथ-साथ जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, सलून्कर विधायक अमृत मीणा, गोंगुदा विधायक प्रताप लाल भील, कुम्भलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मावली में डी.एम.एफ.टी. मद से 442 लाख की लागत से नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया।

चुनाव आयोग ने केन्द्रीय बलों की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जवानों की संवेदनशील व अति-संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव पूर्व तैयारी के लिए रवाना किया गया। ये जवान रेल व सड़क मार्ग से अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। सी.ए.पी.एफ. की प्रथम यूनिट्स इस सप्ताह के अंत में ऐसे राज्यों में पहुंचना शुरू कर देगी जो वामपंथी अतिवादीयों (एल.डब्ल्यू.ई.) से प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल और जम्मू व कश्मीर को छोड़कर। द्वितीय चरण में चुनाव के लिए सशस्त्र कंपनियों को तैनात करने का कार्य 7 मार्च से शुरू किया जाएगा। इसके बाद मार्च के दूसरे व तीसरे सप्ताह में बची हुई कुछ अंतिम यूनिटों को उनके निर्धारित स्थानों पर भेजा जाएगा।

सशस्त्र पुलिस बल यूनिटों को प्रस्थान के आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा उन्हें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें चुनाव आयोग के चुनाव संबंधी सामान्य नियमों की जानकारी के साथ ही सुरक्षा बलों को उन चुनाव ड्यूटी वाले ख़ास क्षेत्रों के बारे में आवश्यक

जानकारी दी जाए ताकि वे उस क्षेत्र के माहौल से भलि-भाति वाकफ हो सकें। प्रथम चरण के तहत सी.ए.पी.एफ. की कंपनियों को विभिन्न प्रदेशों में कानून व्यवस्था को लागू करने में मदद के लिए तैनात किया जा रहा है और जो कंपनियां प्रशिक्षण अभ्यास के लिए आरक्षित हैं उन्हें भी वहां भेजा जा रहा है। सशस्त्र बलों की यूनिट्स को नियमित ड्यूटी जैसे सीमा की सुरक्षा में लगाया है और उन सुरक्षा जवानों को वापस बुलाया जाएगा और उन्हें बाद के चरण में तैनात किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा व सिक्किम विधानसभा के चुनाव भी साफ करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के वास्ते सी.ए.पी.एफ. एवं राज्य पुलिस की अधिकतम 3,400 कंपनियों की मांग की है। चुनाव आयोग चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराने की तारीखों का ऐलान इस माह में बाद में 13 मार्च के बाद किसी भी दिन कर सकता है।

एन.सी.पी. (शरद पवार) शिव सेना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) खासियत है वे कभी भी हार नहीं मानते हैं। उन्होंने बारामती में मुख्यमंत्री शिंदे, अजीत पवार और देवेन्द्र फडनवीस को शनिवार को रात्रि-भोज के लिए आमंत्रित किया है। अब वे शिंदे और पवार की असुरक्षा की भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, फडनवीस ने निमंत्रण अस्वीकार दिया है लेकिन, शिंदे और पवार को तरफ से कोई जवाब

नहीं आया है। अगर यह बैठक हो जाती है तो शरद पवार, सबसे पहले तो अपने भतीजे अजीत पवार को बारामती में दोस्ताना लड़ाई के लिए मनाने की कोशिश करेंगे जिससे सुप्रिया सुले आसानी से जीत सकें। अजीत अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती से चुनाव लड़ाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र राजनीति की उभरती तस्वीर पर चर्चा होने की संभावना है।

प्र.मंत्री मोदी और अमित शाह ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जोशी, कोडरमा से अननपूर्णा देवी, छत्ता से सुनील कुमार, गोड्डा से निशिकांत दुबे और खुंटी से अर्जुन मुण्डा। पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के प्रत्याशियों के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि पंजाब में अकाली दल, आंध्र में तेलुगु देवम पार्टी और जन सेना तथा तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के साथ चुनावी गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। केन्द्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देवेन्द्र फडनवीस, प्रकाश जावड़ेकर, भूपेन्द्र यादव और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि यू.पी. के पूर्व सी.एम. जगदम्बिका पाल

बिजली गिरने से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गिरदावरी करवाकर फसल खराबे का आकलन करने के भी निर्देश दिए। बिजली गिरने से सर्वाइ माधोपुर जिले में 4 व्यक्तियों की मृत्यु व 1 के घायल होने, दोसा जिले की लालसोट तहसील में 2 व्यक्तियों की मृत्यु एवं जयपुर जिले की चाकसू तहसील में 1 महिला की मृत्यु व 1 व्यक्ति के घायल होने की सूचना अब तक प्राप्त हुई है।

निलम्बित पुलिस अफसर मनीष अग्रवाल पर अब मुकदमा चलेगा

जयपुर, 1 मार्च (का.सं.)। हाईवे निर्माण कंपनी से दलालों के जरिए वसूली करने से जुड़े मामले में दौसा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल के खिलाफ ए.सी.बी. कोर्ट में केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से पेश अभियोजन स्वीकृत पेश की।

इसके साथ ही ए.सी.बी. ने नांगल राजावतान थाने के पूर्व थाणाधिकारी कृष्ण कुमार मीणा और सिपाही सुमेश सिंह को लेकर क्लोजर रिपोर्ट दी है। अभियोजन स्वीकृति मिलने पर अब मनीष अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलेगा। मामले में राज्य सरकार की ओर से 2 नवंबर, 2022 को ही अभियोजन की मंजूरी मिल गई थी, जबकि केन्द्र के गृह

केन्द्रीय मंत्रालयों में निजी क्षेत्र के 25 नामी प्रोफेशनल्स की नियुक्ति होगी

नई दिल्ली, 1 मार्च। केन्द्र सरकार निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञों को केन्द्रीय मंत्रालय के प्रमुख पदों पर नियुक्त करने वाली है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में तीन संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों/उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आमतौर पर, संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पद अखिल भारतीय सेवाओं के तहत, संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर भर्तियों की जाती हैं। इन स्तरों पर अधिकारी नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो अधिकारी इस प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं, वे सरकारी प्रणाली का अभिन्न अंग बन जाते हैं।

केन्द्र व राज्य सरकार की तरफ से ए.सी.बी. को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है।

आरोप है कि, मनीष अग्रवाल जब दौसा में पुलिस अधीक्षक थे तब उन्होंने एक हाईवे निर्माण कंपनी से दलालों के जरिए वसूली की थी। मामला सामने आने के बाद 2 फरवरी 2021 को मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया तथा निलम्बित भी कर दिया गया था।

मंत्रालय ने गत 19 जनवरी को अभियोजन स्वीकृति दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार मनीष अग्रवाल ने दौसा एम.पी. रहने के दौरान दिल्ली-बड़ोदरा एक्सप्रेस वे का निर्माण करने वाली कंपनी से दलाल नीरज मीणा के जरिए रिश्वत राशि वसूली थी। ए.सी.बी. ने मनीष अग्रवाल को 2

सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रु. के निवेश से तीन और सेमीकण्डर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी

केन्द्र सरकार ने घोषणा की कि, अगले 100 दिनों के भीतर तीनों इकाइयों का निर्माण शुरू हो जाएगा

नई दिल्ली, 29 फरवरी (वार्ता) सेमीकंडक्टर के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते हुये केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 125600 करोड़ रुपये के निवेश और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 80 हजार रोजगार के अवसर सृजित करने वाली तीन और सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहां हुयी बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के तहत तीन सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी अगले 100 दिनों के भीतर तीनों इकाइयों का निर्माण शुरू हो जाएगा।

भारत में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम दिसंबर 2021 में कुल 76 हजार करोड़ रुपये के व्यय के साथ अधिसूचित किया गया था। जून, 2023 में मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए माइक्रोन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इस इकाई का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है और इकाई के पास एक मजबूत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र बन उभर रहा है।

इसको लेकर जारी बयान में कहा गया है कि, आज की घोषणा के साथ उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों को भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। ये इकाइयों 20 हजार उन्नत

इन्में से एक यूनिट टाटा ग्रुप तैयार करेगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (टी.ई.पी.एल.) लाइवान के पावरचिप सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग कॉर्प (पीएसएमसी) के साथ साझेदारी में एक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगी। इस फैब का निर्माण गुजरात के धोलेरा में किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी नौकरियों का प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 60 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगी। ये इकाइयों डाउनस्ट्रीम ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, दूरसंचार विनिर्माण, औद्योगिक विनिर्माण और अन्य सेमीकंडक्टर उपभोक्ता उद्योगों में रोजगार सृजन में तेजी लाएंगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईपीएल) लाइवान के पावरचिप सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग कॉर्प (पीएसएमसी) के साथ साझेदारी में एक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगी। इस फैब का निर्माण गुजरात के धोलेरा में किया जाएगा। इस फैब में 91,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। पीएसएमसी मेमोरी फाउंड्री सेगमेंट में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। पीएसएमसी की ताद्वार में छह सेमीकंडक्टर फाउंड्री हैं। इसकी क्षमता प्रति माह 50,000 वेफर स्टार्ट (डब्ल्यूएसपीएम) होगी। इसमें 28 एनएम तकनीक के साथ उच्च प्रदर्शन कंप्यूट चिप बनेगा जो इलेक्ट्रिक वाहनों (इवी), दूरसंचार, रक्षा, ऑटोमोटिव, उद्योगीक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्प्ले, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के लिए पावर प्रबंधन चिप के तौर पर उपयोग किया

जा सकेगा। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (टीएसएटी) असम के मोरीगांव में 27 हजार करोड़ रुपये के निवेश से एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगी। टीएसएटी सेमीकंडक्टर फ्लिप चिप और सेमीकंडक्टर फ्लैट चिप (पैकेज में एकीकृत प्रणाली) प्रौद्योगिकियों सहित स्वदेशी उन्नत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है। इसकी क्षमता 4.8 करोड़ दैनिक इकाइयों के लिए है। टीएसएटी, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फोन आदि में उपयोग होंगे।

सीजी पावर, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, जापान और स्टारस माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, थाईलैंड के साथ साझेदारी में गुजरात के साणंद में 7600 करोड़ रुपये के निवेश से एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगा। रेनेसास एक अग्रणी सेमीकंडक्टर कंपनी है जो विशेष चिप पर केंद्रित है। यह 12 सेमीकंडक्टर सुविधाएं संचालित करता है और पतलागिरी, माइक्रोकंट्रोलर, पावर और सिस्टम ऑन चिप (एसओसी) उत्पादों में एक महत्वपूर्ण कंपनी है।

'जमानत के लिए हाई कोर्ट जाओ'...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी 2022 में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में हाई कोर्ट को इस मामले की सुनवाई का भी आदेश दिया।

आसाराम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया कि महाराष्ट्र की पुलिस हिरासत में बंद उनके मुकदमाल

को आर्योदिक ईलाज लेने की इजाजत प्रदान की जाए। इस अनुरोध पर कोर्ट ने वकील से कहा कि यह निवेदन भी राजस्थान उच्च न्यायालय में किया जाए जोधपुर ट्रायब्यूनल की एक कोर्ट ने आसाराम को उनके आश्रम में साल 2013 में एक नवार्जित लड़की से बलात्कार करने के आरोप में अदालत ने दोषी करार देते हुए वर्ष 2018 में

आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी मुकदमें में उनके दो साथियों को कोर्ट ने 20 साल की जेल की सजा सुनाई थी।

जनवरी 2023 में, आसाराम को उनको गुजरात स्थित आश्रम में एक सुप्रीम न्यायाधीश के साथ वर्ष 2013 में बलात्कार करने के आरोप में सजा सुनाई थी।

आर.एस.एस की बैठक 15 मार्च को

नई दिल्ली, 1 मार्च। लोकसभा चुनावों की रणभेरी बजने ही वाली है। इसके ठीक पहले आर.एस.एस. की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की महत्वपूर्ण बैठक नागपुर में होने जा रही है। यह तीन दिवसीय बैठक 15-17 मार्च को विदर्भ के नागपुर में होगी। इस बैठक में आरएसएस के संगठन संबंधित कार्यों पर भी चर्चा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हो सकते हैं।

आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आवेकर ने बताया है कि, इस बैठक में वर्ष 2023-24 के संघ कार्य में सीमाक्षी का जायेगी। इसके साथ ही आगामी वर्ष (2024-25) के लिए आरएसएस के कार्यों की योजना पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि, आरएसएस के विभिन्न सहयोगी संगठनों के लगभग 1500 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के आरामभंग में सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार पर भारी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। अपने परिचित कटाक्ष पूर्ण अंदाज में उन्होंने कहा कि लोगों ने इतना पैसा फिक्रमें तो भी नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा कि मोदी इन भ्रष्ट नेताओं को छोड़ना नहीं क्योंकि, वह इन भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा उद्धारकर्ता हैं। शम को प्रधानमंत्री कलकत्ता पहुंचे यहां राज भवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मोदी ने रक्षात्मक अंदाज में नजर आई उन्होंने प्रश्नकारों से कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ गपशप की।

प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग से बाहर आने पर मुख्यमंत्री ने राजभवन के बाहर एकत्रित प्रश्नकारों के सवालों का जवाब

बड़ी निम्नता से दिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से मुलाकात प्रोटोकॉल का हिस्सा थी हमने अनौपचारिक वार्ता की। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने कहा कि यह मुलाकात दोनों दलों की सांठगांठ को दर्शाती है। इसी बीच सत्तारूढ़ पार्टी में कूटनीतिक घड़ियां भी शुरू हो गईं। तृणमूल महासचिव और पार्टी के दौरे प्रवक्ता कुणाल घोष ने पार्टी के दौरे पदों से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बड़े नेता निजी स्वार्थ के खातिर पार्टी के हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं। घोष ने कहा कि, 80 साल के सुदीप बंदोपाध्याय भी शेरजैसे हैं। उनकी भाजपा से सांठगांठ है, उनके सचिव का बेटा उत्तरी कलकत्ता में भाजपा की जिला इकाई का प्रमुख है। ऐसे लोग राज्य में भाजपा से लड़ सकते हैं। वरिष्ठ नेता सुगत राय ने भी आगामी चुनावों को लेकर निराशा जाहिर की।

टाइम्स नाओ, नवभारत, आज तक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रश्नों से यह स्पष्ट है। जब कुछ पैनलिस्ट्स ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कुछ कथित घटनाओं को साम्प्रदायिक रंग दिया जा रहा है और जिन घटनाओं में अपराधी एक सम्प्रदाय विशेष से ताल्लुक रखता है, वहां महिला हिंसा की घटनाओं को प्रमुखता से उछाला जा रहा है, तो एंकर ने उन्हें डांटकर चुप कर दिया और उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी। एन.बी.डी.एस.ए. ने कहा कि "भविष्य में होने वाले ब्रांडकास्टर्स में "लव जिहाद" शब्द का इस्तेमाल गंभीर आपत्परिक्षण के बम हो कर सकता है।" जब कथित लव जिहाद के बारे में पूछा गया तो गृह मंत्रालय ने 4 जनवरी 2020 को संसद में अपने एक लिखित उत्तर में कहा था कि "लव जिहाद" प्रचलित कानूनों में परिभाषित नहीं है। किसी भी केन्द्रीय एजेंसी ने "लव जिहाद" के किसी केस की रिपोर्ट नहीं दी है।" उसने यह भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धर्म को अंगीकार करने, उसका पालन और प्रचार करने की अनुमति देता है। केरल हाई कोर्ट सहित विभिन्न कोर्टों ने ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि नैशनल इन्वैस्टिगेशन एजेंसी (एन.आई.ए.) ने अन्तर धार्मिक विवाह के दो केसों की जांच की है।

भारतीय टी.बी. न्यूज चैनल में घणास्पद कन्टेंट की भरमार, पिछले कुछ वर्षों से चिंता का विषय रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 में भारतीय मीडिया में भड़काऊ भाषणों की भरमार के एक मामले में सुनवाई करते हुए इसका कारण दर्शकों या श्रोताओं को बताया था। एक जज ने टिप्पणी की थी कि "हेट से 'हेट से' आर.पी. और प्रॉफिट बढ़ाते हैं।" एन.बी.डी.एस.ए. ने 2 मार्च 2023 को तीन टी.बी. न्यूज चैनल को आदेश दिया था कि वे अपने कार्यक्रमों को प्रसारण से हटा लें। ज़ी टी.वी. के अलावा उनमें से दो चैनल न्यूज 18 इण्डिया और टाइम्स नॉट टो आदतन गलतियां करने वाले थे। उनसे कहा गया था कि वे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व यूट्यूब से कम से कम सात कार्यक्रमों को हटा दें क्योंकि इनसे "कोड ऑफ पृथिव्स एण्ड ब्रांडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स" का उल्लंघन हो रहा था।

द न्यूज ब्रांडकास्टर्स एण्ड डिजिटल एंजोसिपेशन (एन.बी.डी.ए.), जिसे पहले न्यूज ब्रांडकास्टर्स एंजोसिपेशन (एन.बी.डी.ए.) के नाम से जाना जाता था, एक सरकारी संस्था ना होकर एक औद्योगिक इकाई है। यह प्राइवेट टेलीविजन न्यूज, कर्नल अफेयर्स और डिजिटल ब्रांडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्वयं को "भारत के डिजिटल ब्रांडकास्टर्स, कर्नल अफेयर्स और न्यूज" की एक सम्प्रदायिक बतौती है। यह एक संगठन है, जिसकी वैबसाइट पर उसके मैम्बर्स पूरी फण्डिंग करते हैं। विशेषतः कहते हैं कि इस आदेश का स्वागत है, लेकिन यह बहुत देर बात उठायी गयी बहुत थोड़ा है क्योंकि हेट प्रोग्राम्स देश के साम्प्रदायिक सौहार्द को पहले ही इतना ज्यादा बिगाड़ चुके हैं कि समाज को उसकी भारी कित्त चुकानी पड़ी है।